(ख) रेलों पर मैत्रीपूर्ण और बेहतर श्रमिक सम्बन्धों की स्थापना के उद्देश्य से मई, 1974 के गैर-कानूनी हड़ताल से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की अपीलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्र निर्णय किया जाता है।

(ग) यद्यपि सरकार की घोषित नीति के अनुसार आम माफी नहीं दी जा सकती फिर भी, अलग-अलग मामलों पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

विवरण

रेलवे	हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सख्या	उन कर्मचारियों की सख्या जिन पर तोड फोड/हिंसा के लिए मुकदमा चलाया गया	उनकी सख्या जिन पर तोड फोड/हिंसा से भिन्न आरोपो के लिए मुकदमा चलाया गया	उन स्थायी/अस्थायी-कर्मचारियों की सख्या जिन्हे अभी तक सेवा मे वापस नही लिया गया है	उनकी संख्या जिनकी सेवा भग माफ नही किया गया है	उनकी सख्या जिनके अभ्यावेदन/अपीले नामजूर कर दी गयी हैं
मध्य .	65,602	65	22	136	254	135
पूर्व .	115,868		..	451	469	321
उत्तर .	38,453	1	9	82	73	80
पूर्वोत्तर	17,506	107	111	28	260	28
पूर्वोत्तर-सीमा	65,000	13	23	262		2
दक्षिण	65,115	41		55	1 626	49
दक्षिण-मध्य	43,748	6	..	19		332
दक्षिणपूर्व	78,869	95	213	449	1,000	332
पश्चिम	72,581	44	5	147	150	93
जोड	562,742	372	383	1,629	3,852	1,040

धनबाद स्थित डी० एस० कार्यालय के अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

*743. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1975 को धनबाद स्थित डी० एस० कार्यालय में काम करने वाले करीब बारह सौ अनुसचिवीय एवं अन्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कौन-सी कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) लगभग 200 व्यक्तियों अधिकांशत भूतपूर्व कर्मचारी और कुछ कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के दौरान मंडल अधिक्षक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किये जाने तथा नारे लगाये जाने की रिपोर्ट मिली है। पता चला है कि इस प्रदर्शन में उन लोगों ने फरवरी में

सिकंदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ की बैठक में लिए गये निर्णयों का स्पष्टीकरण किया तथा 17–3–75 और 18–3–75 को संसद के सामने प्रस्तावित सामूहिक भूख हड़ताल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बर्खास्त किये गये रेल कर्मचारियों को पुन: बहाल किये जाने तथा रेल कर्मचारी संघर्ष राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ आगे बातचीत करने के बारे में भी नारे लगाये।

(ग) बर्खास्त किये गये/सेवा से हटाये गये लगभग 16,700 कर्मचारियों में से लगभग 15,200 कर्मचारी पुन: बहाल किये जा चुके हैं। अन्य अपीलों पर विचार किया जा रहा है।

सरकार ने कभी भी रेल कर्मचारी संघर्ष राष्ट्रीय समन्वय समिति को मान्यता प्रदान नहीं की है, लेकिन बातचीत के लिए रेलों के दो मान्यता प्राप्त महासंघों का सदा स्वागत करती है।

Recommendations of working group of B.I.C.P.

*744. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government have finally decided on the implementation of the recommendations of the Working Group of the Bureau of Industrial Costs and Prices regarding prices of essential drugs; and

(b) if so, the broad outlines of the decision taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. R. GANESH): (a) and (b) The recommendations of the Working Group of the BICP in regard to the first two of the following three terms of their reference have already been adopted by the Government and a statement to that effect was laid on the Table of the Lok Sabha on the 19th April, 1974:—

(i) To study cost structure of 25 bulk drugs and to recommend fair selling prices therefor;

(ii) To review the norms for conversion costs and packaging as prescribed by Government and to recommend the extent to which these require to be modified having regard to the representations received and the objectives of the Drugs (Prices Control) Order, 1970; and

(iii) To study any other items germane to the study of the above matters.

As regards item (iii) above, Government had constituted a Committee on Drugs & Pharmaceutical Industry and one of the terms of the Committee was:

"To examine the measures taken so far to reduce the prices of drugs for the consumer, and to recommend such further measures as may be necessary to rationalise the prices of basic drugs and formulations"

As it was felt that some of the ancillary recommendations of the Working Group may also have a bearing on the conclusions of the Committee it was decided to await the report of the Committee. The Committee has submitted its report to the Government on 6-4-1975 and the matter is receiving attention.

Free Railway pass for office bearer of "convention of Teenagers"

*745. SHRI R. N. BARMAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a free first class All India Railway pass has been issued to one of the office bearers of "Convention of Teenagers", New Delhi;

(b) if so, the name and designation of the person concerned and reasons for issuing the pass;

(c) whether the question of discontinuing this free pass to the said person is under consideration with Railway Board; and